भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 77

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

77. श्री महेश साहू:
श्री सी.पी. जोशी:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री राहुल कस्वां:
श्री सुनील कुमार मंडल:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादन में वृद्धि के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कोयले का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विभिन्न किस्म के कोयले का जोन और राज्य-वार कुल भंडार कितना है;

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले की वास्तविक खपत कितनी है और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने कोयले का उत्पादन और उपयोग किया गया है;

(च) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि दर वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान नकारात्मक थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद की गई कोयला खानों का ब्यौरा क्या है और कोयला निकालने का काम पूरा होने के बाद कितनी कोयला खदान बंद होने की संभावना है; और

(ज) क्या सरकार ने नए खनन क्षेत्रों की संभावनाएं तलाशने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। इसने देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने और कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन शामिल हैं ताकि कैप्टिव खानों को अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने, एमडीओ मॉडल के माध्यम से उत्पादन, आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे सतही खनिक, सतत खनिक आदि के बढ़ते उपयोग, नई परियोजनाओं को शुरू करने और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार तथा निजी कंपनियों/पीएसयू को कोयला ब्लॉकों की नीलामी करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति मिल सके।

राज्य-वार कोयले की उत्पादन योजना निम्नानुसार है:

राज्य	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
(1) छत्तीसगढ़	201.32	224.11	250.70	287.71
(2) झारखंड	165.38	184.27	217.52	263.34
(3) मध्य प्रदेश	130.92	142.63	151.59	158.59
(4) महाराष्ट्र	62.39	64.98	67.97	69.53
(5) ओडिशा	211.50	238.20	273.04	350.41
(6) पश्चिम बंगाल	36.68	37.95	42.96	47.17
(7) तेलंगाना	69.82	72.50	75.30	78.14
(8) उत्तर प्रदेश	*33.00*	*32.50*	*32.50*	*33.50*
कुल योग	**911.00**	**997.14**	**1111.60**	**1288.39**

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**कोयले का आयात (मि.ट.)**	**मिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य**
2019-20	248.54	21387.28

2020-21	215.25	15665.39
2021-22	208.93	30623.81

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, कोयले का आयात 2019-20 में 248.54 मि.ट. से घटकर 2020-21 में 215.25 मि.ट. और 2021-22 में 208.93 मि.ट. हो गया है। 2021-22 में कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में भी तेजी से वृद्धि हुई और चालू वर्ष में भी उच्च बनी रही। आम तौर पर, अनिवार्यता और घरेलू आपूर्ति-मांग का अंतर आयात किए जाने वाले कोयले की मात्रा निर्धारित करता है। कोविड वर्ष 2020-21 के दौरान, कोयले की कुल मांग, जो मामूली रूप से कम हुई है, को कोयले की घरेलू आपूर्ति में कमी और आयात में कमी दोनों से पूरा किया गया। 2021-22 में जहां कोयले की कुल मांग में 13.4% की वृद्धि हुई है, वहीं कोयले की घरेलू आपूर्ति में 18.5% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में इस बढ़ी हुई घरेलू कोयले की आपूर्ति को कोयले के आयात को कम करने वाले निर्धारकों में से एक कहा जा सकता है। इसलिए, सैद्धांतिक रूप से, लगभग 40-50 मि.ट. के कीमत के विदेशी मुद्रा कोयले की बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय कीमत पर बचाई गई कही जा सकती है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**कोयले का उत्पादन (मि.ट.)**
2019-20	730.87
2020-21	716.08
2021-22	778.19

(घ): दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार कोयले और लिग्नाइट की इन्वेंट्री के अनुसार, कुल अनुमानित भूगर्भीय कोयला संसाधन 361411.46 मिलियन टन है। ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय कोयले की खपत नीचे दी गई है: -

(मिलियन टन में)

वर्ष	**कुल खपत**
2019-20	955.72
2020-21	906.13
2021-22	1027.92

कैप्टिव खानों से कोयला उत्पादन सहित पश्चिम बंगाल (प.बं.) में कोयला उत्पादन और प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल में सीआईएल उत्पादन	पश्चिम बंगाल के लिए सीआईएल का प्रेषण	पश्चिम बंगाल में कैप्टिव खानें	प. बं. द्वारा कोयले की खपत
2021-22	28.99	49.02	4.43	53.45
2020-21	30.30	51.00	4.21	55.21

(च): वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत नकारात्मक थी। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	सीआईएल का उत्पादन (मि.ट.)	वृद्धि %
2018-19	606.89	
2019-20	602.13	-0.78
2020-21	596.22	-0.98

कोयला उत्पादन में प्रमुख बाधाओं में भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि के वास्तविक कब्जे में देरी, आरएंडआर मुद्दे, अतिक्रमण के मुद्दे, वानिकी और पर्यावरण मंजूरी में देरी, निष्कर्षण और लॉजिस्टिक्स बाधाओं तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या शामिल हैं।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले की मांग में कमी आई, जिसने सीआईएल से कोयले के प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उच्च पिट हेड कोयला भंडार, विद्युत गृहों में पर्याप्त कोयला भंडार और कम उठाव के कारण कोयला उत्पादन को विनियमित किया गया था।

कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

<u>भूमिगत (यूजी) खानें</u> :

अधिकांश यूजी खानें जो सीआईएल को पूर्व की राष्ट्रीयकरण अवधि से विरासत में मिली थीं, ज्यादातर अत्यधिक श्रमिक उन्मुख थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद से, सीआईएल की यूजी खानों को धीरे-

धीरे अर्ध-मशीनीकृत खानों और मशीनीकृत खानों में, जहां भी तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, परिवर्तित किया जाता है। मशीनीकृत व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी (एमपीटी) को जहां भी भू-खनन की स्थिति अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में, 2 खानों को पावर्ड सपोर्ट लॉन्ग वॉल प्रौद्योगिकी के साथ काम में लाया जा रहा है तथा 2 और खानों को इस प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वर्तमान में 14 खानों में 21 सतत खनिक (सीएम) प्रचालनरत हैं और अपनी सभी सहायक कंपनियों में 5-6 वर्षों के भीतर 100 से अधिक सीएम शुरू करने की उम्मीद है। इसके अलावा, सीआईएल यूजी खनन के माध्यम से अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाईवॉल माइनर्स (एचडब्ल्यू) को मजबूत रूप से शुरू करने का इरादा रखती है और 5-6 वर्षों के भीतर कम से कम 50 अतिरिक्त एचडब्ल्यू माइनर्स को शुरू करने की परिकल्पना करती है।

इसके अलावा, भूमिगत खानों में, मूल रूप से अधिक जोर कोल विनिंग/लोडिंग सिस्टम, कोल ड्रिलिंग एंड सपोर्टिंग सिस्टम, कोल इवैक्युएशन सिस्टम आदि के मशीनीकरण पर दिया गया है। सीआईएल में, लगभग सभी मैनुअल लोडिंग को मैकेनाइज्ड लोडिंग सिस्टम में बदल दिया गया है। कोयला उत्पादक कंपनियाँ धीरे-धीरे मैनुअल ड्रिलिंग को यूडीएम ड्रिलिंग, परिवहन की ढुलाई प्रणाली से कन्वेयर सिस्टम तक, जहाँ भी व्यवहार्य हो, परिवर्तित कर रही हैं।

<u>ओपन कास्ट (ओसी) खानें</u> :

सीआईएल ने मशीनीकरण की शुरूआत के माध्यम से अपने ओसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां इकोनोमी ऑफ स्केल का लाभ उठाने के लिए भारी मशीनीकरण के साथ उच्च क्षमता वाली खानों (क्षमता> 10 एमटीवाई) को शुरू कर रही हैं।
- सीआईएल ने अपनी कार्य क्षमता में सुधार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी भी शुरू की है। गेवरा एक्सपेंशन ओसी, दीपका ओसी और कुसमुंडा ओसी जैसी अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं में 240 टी रियर डम्पर के साथ 42 कम शॉवेल जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम को शुरू किया गया है।
- प्रचालन दक्षता में सुधार लाने और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सतही खनिकों को ओपनकास्ट खानों में बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, सीआईएल के कुल उत्पादन का 50% से अधिक का उत्पादन सतही खनिक के माध्यम से किया गया है और बाद के वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

इसके अलावा, सीआईएल ने प्रचालन के डिजिटलीकरण और ईआरपी की शुरूआत के साथ अपनी खानों की दक्षता बढ़ाकर अपने उत्पादन को बढ़ाने की पहल की है।

(छ): पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार परित्यक्त/बंद/समाप्त कोयला खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सहायक कंपनी	खानों का नाम
ईसीएल	सोदपुर (आर)
	न्यू केंडा
	बेरा
	केंदुआडीह
	भागबंद
बीसीसीएल	पीबी परियोजना
	केबी 10/12 पिट्स
	डोबारी
	भौरा (एन)
	शोभापुर
	घोरावारी / झरना
	बरकुही ओ.सी
	भरत (घोरावरी-2)
डब्ल्यूसीएल	कुम्भारखानी
	पिपला
	एबी इनक्लाइन
	सीआरसी
	विष्णुपुरी -I
	गणपति
	पिनौरा
एसईसीएल	पश्चिम चिरिमिरी
	महामाया
	बिश्रामपुर
	महान
	महान-II
	कटकोना 3 और 4
एमसीएल	ओरिएंट -3
एनईसी	तिपोंग
	तिरप

कोयला निकासी का कार्य पूरा होने के बाद जिन खानों के बंद होने की संभावना है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

सहायक कंपनी	**खानें जो कोयला निकासी का काम पूरा होने के बाद बंद हो सकती हैं**
ईसीएल	शंकरपुर यूजी, गोपीनाथपुर ओसी
बीसीसीएल	शून्य, कुछ खानों में कोयला निष्कर्षण कार्य पूरा होने के बाद आगामी वर्षों में कोयले के भंडार समाप्त हो सकते हैं, परंतु बाहरी ओबी डंपिंग आदि जैसे प्रचालन में सरलता लाने के लिए ऐसी खानों को परिधि में मौजूदा खानों के साथ समामेलित किए जाने की संभावना है।
सीसीएल	शून्य
एनसीएल	काकरी ओसीएम
डब्ल्यूसीएल	सतपुड़ा II यूजी और पाथाखेड़ा I यूजी
एसईसीएल	उत्तर चिरिमिरी यूजी, माल्गा यूजी, पिनौरा यूजी
एमसीएल	शून्य
एनईसी	शून्य

(ज): देश में नए कोयला भंडार/नए खनन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोयला मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण की एक उप-योजना है। सीएसएस फंडिंग के माध्यम से क्षेत्रीय कोयला ब्लॉकों में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान किए गए ड्रिलिंग की कुल लंबाई नीचे तालिका में दी गई हैः-

वित्तीय वर्ष	**ड्रिलिंग मीटरेज (लाख मी.)**
2020-21	1.12
2021-22	1.55
2022-23 (अप्रैल, 22-अक्टूबर, 22)	0.41

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से सीएमपीडीआई द्वारा जोड़े गए कुल नए कोयला संसाधन नीचे तालिका में दिए गए हैं;

वित्तीय वर्ष	**कोयला संसाधन (बिलियन टन)**
2020-21	1.33
2021-22	5.71

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2021-22 से एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से नए कोयला भंडार का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण भी शुरू कर दिया है। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से क्रमश: 0.025 लाख एम और 0.069 लाख एम ड्रिलिंग की है।

जीएसआई नए कोयला संसाधनों की पहचान के लिए खान मंत्रालय के तहत कोयले का क्षेत्रीय अन्वेषण भी कर रहा है। जीएसआई से डाटा मांगा जा सकता है।

****

अनुबंध- I

जीएसआई द्वारा दिनांक 01.04.2022 को प्रकाशित भारत की कोयला सूची के अनुसार देश में कुल अनुमानित ग्रेड-वार कोयला संसाधन नीचे दिए गए हैः-

(संसाधन मिलियन टन में)

कोकिंग			गैर कोकिंग				
मुख्य	मध्यम	अर्ध कोकिंग	उच्च स्तर का (जी1-जी6)	निम्न स्तर का (जी7-जी17)	अनग्रेड	उच्च सल्फर	कुल योग
5318.29	28079.59	1707.52	39113.63	261371.24	24165.65	1655.54	361411.46

जीएसआई द्वारा 01.04.2022 को प्रकाशित भारत की कोयला सूची के अनुसार देश में अनुमानित राज्य-वार कोयला संसाधन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

भारतीय कोयला संसाधन का राज्य-वार ब्यौरा

(संसाधन मिलियन टन में)

राज्य	मापित (331)	निर्दिष्ट (332)	अनुमानित (333)	संसाधन
ओडिशा	48572.58	34080.42	5451.60	88104.60
झारखंड	53245.02	28259.67	5155.41	86660.10
छत्तीसगढ़	32053.42	40701.35	1436.99	74191.76
पश्चिम बंगाल	17233.88	12858.84	3778.53	33871.25
मध्य प्रदेश	14051.66	12722.97	4142.10	30916.73
तेलंगाना	11256.78	8344.35	3433.07	23034.20
महाराष्ट्र	7983.64	3390.48	1846.59	13220.71
बिहार	309.53	4079.69	47.96	4437.18
आंध्र प्रदेश	920.96	2442.74	778.17	4141.87
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0.00	1061.80
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48
असम	464.78	57.21	3.02	525.01
नागालैंड	8.76	21.83	447.72	478.31
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
कुल	**187105.32**	**147252.18**	**27053.96**	**361411.46**